LOK SABHA

*Tuesday, April 15, 1975/Chaitra 25, 1897 (Saka)*

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

MOTION *REG.* SUSPENSION OF QUESTION HOUR

Mr. SPEAKER : Shri Janeshwar Misra, you have given notice for suspention of the question hour. You have set a very bad practice.

**श्री जनेश्वर मिश्र** (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आप जरा हमारी बात सुनलें कि यह प्रस्ताव हमने क्यों दिया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह बहुत ही बैड प्रैक्टिस है कि जो बात वैसे न आ सकती हो उस को इस तरह से लें आयें।

**श्री जनेश्वर मिश्र** : अध्यक्ष महोदय, 7 लोग मारे गये हैं। लेवी वसूल करने के सिलसिले मे उड़ीसा में पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। वहां के अधिकारियो ने गांवो के लोगो पर अत्याचार किये जिस की वजह से 7 लोग मारे गये हैं। हम समझते है कि यह बहुत ही अहम मसला है। जब इस स्थिति हो तो क्वेश्चन आवर में हम क्या बहस करें। किसानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो तों हम चाहेंगे कि क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया जाय और इस अहम मसले पर विचार किया जाय।

**अध्यक्ष महोदय** : यह स्टेट मैटर है, केन्द्र से इस का कोई ताल्लुक नहीं है।

**श्री जनेश्वर मिश्र** : है क्यों नहीं? केन्द्र के आदेशानुसार ही तो राज्यों मे किसानों से लेवी वसूल की जा रही है जिस के चलते राज्य सरकारें जबरदस्ती अपने यहां की जनता पर गोली चला रही हैं।. . . (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : यह बहुत ही खराब प्रैक्टिस है। आप बैठिए। देखिए आप ने क्वेश्चन आवर को सस्पेंड करने के लिये कहा है। अब यह एक नई नीति चला दी जो अच्छी नहीं है। जो बात केन्द्र से संबंधित न भी हो उस पर क्वेश्चन आवर को सस्पेंड करने का प्रस्ताव ले आना, यह अच्छी बात नहीं है। और किसलिये क्वेश्चन आवर सस्पेंड करें? ऐसे मसले के लिये जो स्टेड का विषय है। ला एंड आर्डर का मसला स्टेट गवर्नमेंट से संबंध रखता है। यह उड़ीसा सरकार से ताल्लुक रखता है न कि हम से। आप को सस्पेंड करवाना है तो तब हो जो कि जो मैटर यहां डिस्कस करना है वह हमारी कम्पीटेंस में हो। यह तो स्टेट मैटर है।

**श्री जनेश्वर मिश्र** : सेन्ट्रल गवर्नमेंट के मन्त्रियों और स्टेट चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में यह लेवी का कानून तय किया गया और उस को रोशनी में राज्य सरकारें जा कर लेवी के लिये लोगो की जान लें, यह कहां तक उचित है।

**अध्यक्ष महोदय** : जो पार्लियामेंट से संबंधित है वही चिज यहां पर उठायी जा सकती है। मैं इस बारे में और कुछ सुनने के लिये तैयार नहीं हूं। एक घंटे का क्वेश्चन आवर है वह भी इस तरह सस्पेंड कर दो। क्या बात है!

**श्री जनेश्वर मिश्र** : अध्यक्ष महोदय, 'ट्रिब्यून' अखबार में मुझे यह खबर पढ़ने को मिली है। अहमदाबाद में 7 लोक लाठी चार्ज से घायल हुए तो वह खबर डबल कालम में छपी। लेकिन किसानों के साथ उड़ीसा सरकार इस प्रकार बर्बतापूर्ण व्यवहार करे और उन पर गोली चलाये उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : कितना गलत तरीका है कि आप एक सस्पेंशन का नोटिस दे कर उस बात पर भाषण देना शुरू कर दें। यह कैसे हो सकता है जब तक कि हाउस उस पर इजाजत नहीं देता।

The subject of law and order in the State of Orissa is not with the Central Government. It is not the Home Minister here who is responsible for that. You are questioning my ruling.

Those in favour of the suspension of the Question Hour shall say 'Aye'.

SOME HON. MEMBERS : Aye.

MR. SPEAKER : Those against shall say 'No'.

SEVERAL HON. MEMBERS : No.

MR. SPEAKER : The Noes have it. This is negatived.

श्री जनेश्वर मिश्र : इस पर हमारा एडजर्नमेंट मोशन भी है।

MR. SPEAKER : We shall take up questions.

---

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### Action on Demands of S & T Staff of Indian Railways

*628. SHRI CHANDRIKA PRASAD Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 250 on the 12th November, 1974 regarding 'work-to rule' agitation by Signal and Telecommunication staff and stage :

(a) whether any further action has been taken on the demands of Signal and Telecommunication staff of Indian Railways ; and

(b) if so, what are the salient features of the action taken so far on each demand ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH) : (a) and (b) Out of the seven demands of the Signal and Telecommunication Staff, final decision remains to be taken on only one demand, viz., that Inspectors should be relieved of the stores responsibilities. This demand is under consideration.

श्री चन्द्रिका प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी के उत्तर से लगता है कि 6 मांग स्वीकार कर ली गई है इसलिये रेल मंत्रालय बधाई का पात्र है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वह 6 मांगे क्या हैं और उन का कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या किया है ?

SHRI BUTA SINGH : Their demands are followas :

They should be treated at par with technical categories of traffic controllers. There should be 8 hours duty for all the staff and this could be done by declaring the S & T staff as continuous under the hours of employment regulation. More staff should be provided as present the staff is inadequate उन को बसटीग पोइंट अलाउन्स दिया जाय जो भी समय लगता है । Inspectors should be relieved of stores responsibilities by posting store keepers All signal staff should be allotted railway quarters. Full uniform for winter and summer should be given to all S & T staff. Negotiating facilities should be given to this category of employees.

श्री चन्द्रिका प्रसाद : कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या किया है, यह मैं जानना चाहता हूं।

SHRI BUTA SINGH : As I said the only demand left is the demand for being relieved of stores responsibilities Decisions have been taken on all other demands and they are at various stages of implementation.

श्री चन्द्रिका प्रसाद : मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि सातवीं मांग पर विचार कर रहे हैं। मंत्रालय ने आश्वासन दिया था कि 6 महीने में विचार कर लेंगे लेकिन डेढ़ वर्ष हो गया है अब मंत्री जी बता दें कि कितना और समय लेंगे ?